किसान - मजदूर एकता जिंदाबाद। गांव का एका जिंदाबाद।। शहीद किसान अमर रहे।।

किसान सघंर्ष समिति

मुख्य कार्या: शहीद किसान स्मृति कुटीर,स्टेशन रोड,मुलतापी,बैतूल (म.प्र.)460661 ईमेल kssmultapi@gmail.com

रामस्वरुप मंत्री (प्रभारी मालवा निमाड)
मों.नं 7999952909

दिनेश सिंह कुशवाह (प्रदेश सचिव)
मो नं . 9179623769

दिनांक-08/12/2020

ज्ञापन पत्र

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली

द्वारा _----------

विषय:- किसान आंदोलन के समर्थन में हो रहे भारत बंद के अवसर किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र।

माननीय महोदय

आप जानते ही हैं कि देश के किसानों द्वारा दिल्ली में 26-27 नवंबर से तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने और बिजली बिल वापस लेने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। पंजाब - हरियाणा - उत्तरप्रदेश के लाखों किसान दिल्ली मेंडेरा डाले हुए हैं। 12 दिन होने के बावजूद अब तक सरकार द्वारा तीनों कानूनों को

रद्द करने एवं बिजली बिल वापस लिए जाने की घोषणा नहीं की है। आपकी सरकार एक तरफ बातचीत कर रही है दूसरी तरफ आपके द्वारा कानूनों के पक्ष में लगातार बयान देकर किसानों को विपक्षियों द्वारा भ्रमित बतलाया जा रहा है।आपके गोदी मीडिया द्वारा किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी ,विपक्षी दलों की कठपुतली ,विदेशी पैसों से आंदोलन चलाने वाला बतलाकर अपमानित किया जा रहा है ।

आज 8 दिसंबर को किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े देश भर के 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है यदि अभी सरकार नहीं खींची होगी वो किसी विधायक वापस नहीं लिए तथा बिजली बिल 2020 संशोधन कानून को लागू करने की कोशिश की तो देशव्यापी किसानों और बढ़ जाएगा उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की होगी

आपके द्वारा जबरजस्ती बनाये गए तीन कृषि कानूनों का मकसद खेती का कार्पोरेटिकरण करना है। हम चाहते हैं कि किसान में खेती करें ।

आप कारपोरेट को खेती सौंपना चाहते हैं। हमारी समझ है कि कानून किसानों की जमीन छीनने के उद्देश्य से लाए गए हैं ताकि किसान, किसानी और गांव खत्म कर कारपोरेट के लिए सस्ते मजदूर उपलब्ध कराया जा सकें।

एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत और किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानूनों के माध्यम से आपने कारपोरेट को खेती में असीमित निवेश करने, कृषि उत्पादों की खरीद करने, भंडारण करने, खाद्य प्रसंस्करण करने तथा कृषि उत्पादों की जमाखोरी करने की खुली छूट दे दी है जिससे मंडी व्यवस्था, एमएसपी व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली (खाद्य सुरक्षा) खत्म होना तय है।

आपकी सरकार द्वारा कोरोना काल में 68 ,000 करोड़ की छूट कारपोरेट को दी गई। आजादी के बाद अब तक कुल 48 लाख करोड की छूट दी जा चुकी है, दूसरी तरफ किसान गत 4 वर्षों से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश के किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति के लिए आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा अब तक संपूर्ण कर्जा मुक्ति नहीं की गई है। जिसमें 14 लाख करोड़ खर्च होंगे।

हम खेती के कारपोरेटीकरणके खिलाफ आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और आपको चेतावनी देने के लिए यह ज्ञापनपत्र सौंप रहे हैं।

किसान सभी कृषि उत्पादों की लागत से डेढ़ गुना मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।आप जानते ही हैं कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से हमारे प्रतिनिधियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में इस आशय का बिल पेश किया जा चुका है।

संसद का विशेष सत्र बुलाकर आप तत्काल किसान विरोधी कानून रद्द करें और किसानों की ओर से प्रस्तावित बिलो को पारित कर कानून बनाएं।

यदि तत्काल किसान विरोधी कानून और बिजली बिल 2020 रद्द नहीं किए गए तो देश भर के किसान भी दिल्ली में डेरा डाले किसानों की तरह हम भी अनिश्चितकालीन आंदोलनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे।

भवदीय

किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़ , एवं धार जिले के सभी लोकतांत्रिक जनवादी संगठनों के साथी

किसान संघर्ष समिति- जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय- अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति -संयुक्त किसान मोर्चा

प्रतिलिपि –

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भारत सरकार

दिनेश सिंह कुशवाह

प्रसन्ना मंडोलिया

कार्य. अध्यक्ष धार